...रोकने का षड्यंत्र, कानपुर में भारी मात्रा में ... और बारूद का पकड़ा जाना, बंबई के एक बैंक ... डकैती, अंतर्राष्ट्रीय तस्करों द्वारा करोड़ों के सोने की ...री, प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान में दस लाख के करों ... चोरी, एक सरकारी निगम के अध्यक्ष द्वारा लाखों ... भ्रष्टाचार, ऐसी असंख्य घटनाएं रहस्य होती हैं. ... बार, पुलिस और सरकार के लिए भारी बोझ से ... जाती हैं. जोर लगा कर इन पर से पर्दा उठाया ... पुलिस को छोटे-मोटे अपराधों की रोकथाम और ... व्यवस्था बनाये रखने के काम से कभी फुरसत ... मिलती नहीं. फिर वह बड़े प्रकरणों की गहराई तक ... कैसे? यदि कोशिश भी करे, तो 'पुलिस' की वर्दी ... कमियों के कारण लोग विश्वास नहीं करते. हां, ... सदस्य हो या विधायक, छात्र हो या संपादक, ... अपने-अपने माध्यम से मांग करते हैं—सी. बी. आई. ... जांच करे की. अपराधों की संख्या में वृद्धि के ... दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है सी. बी. आई. का ... और महत्व. सी. बी. आई. यानी केंद्रीय अन्वेषण ... यों भी अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय अपराध होने ... राज्य सरकार सी. बी. आई. की सहायता ... हैं. किंतु प्रमुख रूप से धोखाधड़ी से राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने के खिलाफ और भ्रष्ट सर-

सच्चाई छुप नहीं सकती : मशीन से संकेत मिल सकते हैं कि अपराधी सच बोल रहा है या नहीं ? पॉलिग्राफ मशीन पर जांच करते सी. बी. आई. के एक प्रमुख सहायक

भ्रष्टाचार निवारक सी. बी. आई

□ आलोक मेहत

...कारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दायित्व ...संगठन पर है.

इस जिम्मेदारी को सफलता से निभाने का अंदाज ...इस से लगाया जा सकता है कि वर्ष १९७३ में ...गुरों की सक्रियता से केंद्रीय राज कोष के लिए लगभग ... करोड़ रुपये की वसूली हुई. यही नहीं, इसने सरकार ... १४६ उच्च राजपत्रित अधिकारियों को भ्रष्टाचार ... आरोप में कटघरे में खड़ा कर दिया.

...संगठन के इस सोपान पर विचार आता है—आखिर सी. बी. आई. का गठन कैसे हुआ? गठन हुआ, तो ...अन्य सरकारी विभागों की तरह 'अस्तव्यस्तता' क्यों नहीं? ... ऐसा क्या कर राष्ट्र को लाभ पहुंचाया, तो किन साधनों और स्थितियों से? युद्धकालीन नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन की जांच के लिए १९४१ में दिल्ली विशेष पुलिस के रूप में एक छोटी सी यूनिट कायम हुई. इसी यूनिट के विस्तार की दृष्टि से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट १९४६ बनाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को संघीय क्षेत्रों में कुछ निश्चित अपराधों की जांच के लिए पुलिस अन्वेषण एजेंसी स्थापित करने का प्रावधान था. बाद में राज्यों की सहमति से इसी संगठन को वहां के कुछ निश्चित अपराधों की जांच के अधिकार दिये गये. संगठन को 'कानून का सबसे बड़ा हथियार' माना गया और कानूनों का उल्लंघन करनेवालों और समाज की घातक 'बड़ी मछलियों' की छानबीन कर उन्हें दंडित करवाने का दायित्व इसे मिला. राज्यों की पुलिस से अधिक अधिकारों एवं साधनों के का... इस विशेष पुलिस को अपराधियों की पकड़-धक... में महत्वपूर्ण सफलताएं मिलने लगीं. किंतु देश में ... यातायात और संचार-साधनों के विकास ने विशेष पुलिस 'जाल' को कमजोर बना दिया. अपराधी आधु... साधनों का लाभ उठा कर चकमा देने लगे. यही ... अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह भारतीय पुलिस की कमज... का फायदा उठाने में सफल हुए.

तब अपराध और अपराधियों पर कड़ी नजर र... के लिए एक बड़े व्यवस्थित जांच संगठन की आवश्य... महसूस की गयी. परिणाम स्वरूप अप्रैल, १९६३ में भा... सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर के सी. बी. आ... (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की स्थापना के लिए अ... स्वीकृति दी. तत्कालीन 'विशेष पुलिस' को सी. ... आई. का ही एक अंग बना दिया गया. हां, सी. ... आई. के अधिकारियों को दिल्ली विशेष संगठन अ... नियम (एस्टेब्लिशमेंट एक्ट) के अंतर्गत जांच करने के अधिकार दिये गये.

चार्टर: सरकारी कर्मचारियों ...
भ्रष्टाचार की प्रामाणिक ज...

सी. बी. आई. की जिम्मेदारियों के संबंध में ... चार्टर बनाया गया. इस चार्टर के अनुसार सी. बी. आ... का पहला काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये ... वाले भ्रष्टाचार को पकड़ना, जांच करना और प्रा...णित आधार पर न्यायालय में अभियोग चलाना ... इस तरह बड़े पैमाने पर हो रही मुनाफाखोरी ... सार्वजनिक संस्थानों में की जानेवाली धोखाधड़ी ... जांच करना और दंड दिलवाना इसी संगठन की जि...दारी है—इनमें डॉ. धर्म तेजा द्वारा की गयी का... की गड़बड़ी का पर्दाफाश करने जैसी जांच ऐतिहा... कही जा सकती है.

गोली किस बंदूक या पिस्तौल से चलायी गयी ? गोली की शक्ति का परीक्षण करते एक हुए विशेषज्ञ

भ्रष्टाचार, तस्करी, घोटाले, जालसाजियां, राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र. . .कौन इनका पर्दाफाश करता है? सी. बी. आई.! पर यह क्या कोई जासूसी संगठन है? आखिर सी. बी. आई. है क्या? कौन इसका संचालन करता है? विभिन्न पहलुओं की जानकारी, प्रामाणिक विवरण, उच्च अधिकारी से भेंटवार्ता.

इसके अलावा पुलिस के प्राथमिक कार्य के रूप सी. बी. आई. देश भर में होनेवाले अपराधों और अपराधियों के विस्तृत आंकड़े और ब्योरा संकलित करती है. वर्ष १९७३ के अंत तक सी. बी. आई. के पास ... अपराधियों के नाम और विवरण थे. केवल एक वर्ष अर्थात १९७३ में इस संगठन ने ... नये अपराधियों का पता लगा कर उनके नाम अपने अभिलेख में जोड़ लिये. इससे किसी भी अपराध का मामला आने पर अपराधियों की खोज में बहुत सहायता मिल जाती है.

इसके अलावा आर्थिक मामलों में संबंधित अपराधों की रोकथाम का दायित्व सी. बी. आई. पर है. ... केंद्र सरकार जिन बड़े अपराधों को रोकना आवश्यक समझती है, विशेषकर अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय ... के लिए घातक अपराधों के महत्वपूर्ण मामले सी. बी. आई. के सुपुर्द कर देती है. साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को रोकने और पुलिस को अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से राज्यों की पुलिस एवं विभिन्न ... कानूनों के अध्ययन और समयानुसार किये जानेवाले परिवर्तनों की सलाह सी. बी. आई. सरकार को देती है.

यही नहीं, सी. बी. आई. राज्यों की पुलिस को जटिल और विवादास्पद प्रकरणों के सुलझाने में विशेष सहायता एवं सलाह देती है. अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में सी. बी. आई. भारत की ओर से इंटरपोल (इंटर नेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन) की सहायता देती है. इसके बदले में इंटरपोल भारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में सहायता देता है.

... व्यक्ति सी. बी. आई. का अधिकारी नहीं

दिल्ली के कॉफी हाउस, बड़े मशहूर हैं—कानाफूसी, गोष्ठियों और मसखरी के लिए. एक दिन ऐसे ही किसी कॉफी हाउस में राजनीतिक उथल-पुथल पर ... गरमागर्म चर्चा के दौरान एक मित्र ने अचानक कहा—"देखो, कोने में वह दाढ़ीवाला बैठा है न! सी. बी. आई. का आदमी है. मैं इसे अधिकांश राजनीतिक ... में देखता हूं." स्वाभाविक था—सब की नजर बोलनेवाले सज्जन की ओर मुड़ी. मुझे चोरों से ... देखने या दिखानेवालों पर नहीं—इस ... पर मैंने उनकी बात का खंडन किया, तो यही ... चर्चा का विषय बन गया. अधिकांश साथी उस मित्र ... हुए कह रहे थे—"हां, भई ऐसा ही होगा. सी. बी. आई. वाले किसी को नहीं बख्शते. . . जो कुछ

ज़हर की पहचान : दूध-का-दूध पानी-का-पानी

टंकित दस्तावेजों की सत्यता का परीक्षण

... की झूठी मुहर : असली-नकली की पहचान

बालों से अपराधी की पहचान : हत्या हो या बलात्कार छोटा-सा बाल भी अपराधी को पकड़वाने में सहायक होता है

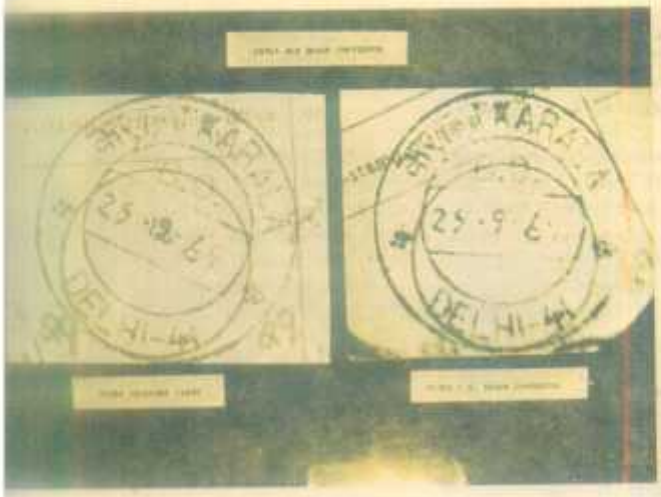

सरकंकाल से वास्तविक अपराधी का सुराग

एक्स-रे द्वारा लकड़ी के डिब्बे में छुपायी गई

बातचीत करो, मोल-भाव कर. वरना ऐसे ही मासूम तुम्हारे घर के आसपास चक्कर काटेंगे और पत्रकारिता धरी रह जायेगी."

इन गंभीर सलाहों के बावजूद मैं हंसता रहा और फिर मैंने उन्हें हंसी का कारण स्पष्ट किया, "जनाब, यह आप लोगों की गलतफहमी है सी. बी. आई. राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में जासूसी नहीं करती. उसका काम सरकार को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पहलुओं का ब्यौरा देना नहीं होता. यह काम करता है इंटेलीजेंस ब्यूरो. अब यह भी बताऊं कि सी. बी. आई. के अधिकारी अपना परिचय दे कर जांच-पड़ताल करते हैं. इंटेलीजेंस का व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा. हां, यदि आप रिश्वत लेते हों, तस्करी में लिप्त रहते हों, कोई बैंक लूट कर भागे हों, तो सी. बी. आई. से डरो. यदि ऐसे अपराधों को रोकना चाहते हो, तो उससे जाकर अपनी जानकारी देकर सी. बी. आई. की सहायता करो. इसका लाभ तुम्हें और हम ही नहीं, सारे समाज को होगा."

युवा मित्रों की उत्सुकता बढ़ी. तब मैंने बताया, "सी. बी. आई. भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन कार्य करता है. जब कि 'इंटेलीजेंस ब्यूरो' की चाबी गृह मंत्रालय के हाथ में होती है. फिर मामला भारत की राजनीति का हो या विश्व कूटनीति का, 'इंटेलीजेंस ब्यूरो' का काम हर देश की राजनीतिक स्थितियों की थाह लेना है. और, इसलिए 'इंटेलीजेंस' या 'सी. बी. आई.' को हम-तुम जैसे लेखकों या पत्रकारों पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. यदि पड़े तो हमें हवा भी नहीं लगेगी."

खैर, मित्रों से हुई यह चर्चा लिखने लगा, तो शायद आप पाठक भी नाराज हो जायेंगे. सी. बी. आई. 'क्या' करता है, इतना अधिक जान लेने के बाद 'कैसे' और 'किन से' का प्रश्न सबके दिमाग में उभरेगा ? तो जवाब हाजिर है.

अपराधों की प्रारंभिक जानकारी, वैधानिक जांच, वैज्ञानिक प्रमाण और कानूनी कार्रवाई के लिए इस समय प्रमुख रूप से सी. बी. आई. के कुछ प्रभाग (डिवीजन) हैं—विशेष पुलिस संगठन प्रभाग, विधि प्रभाग, नीति प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, अपराध अभिलेख प्रभाग, सांख्यिकी प्रभाग, इंटरपोल प्रभाग और प्रशासन प्रभाग. अपराधविज्ञानी वैज्ञानिक परीक्षण, प्रयोग एवं शोध के लिए 'फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी' सी. बी. आई. की महत्वपूर्ण सहायता करती है.

विशेष पुलिस प्रभाग के तीन खंड हैं. जो आर्थिक मामलों, सामान्य अपराधों और खाद्य पदार्थों की तस्करी संबंधी प्रकरणों का पता लगा कर जांच करने और न्यायालय के सुपुर्द करने का दायित्व संभालते हैं. सामान्य अपराधों-संबंधी खंड सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार-प्रकरणों, पासपोर्ट की जालसाजी, प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले अपराधों, रेलवे, डाक-तार और समुद्री या वायु परिवहन व्यवस्था को धोखा देने के मामलों की जांच करता है.

आर्थिक मामलों से संबंधित खंड वित्त मंत्रालय के सहयोग से चुंगी कर, आय कर, आयात-निर्यात, विदेशी मुद्रा, अफीम और खतरनाक औषधि अधिनियमों एवं ऐसे अन्य कानूनों के उल्लंघन और गड़बड़ीवाले, नकली नोट बनाने या अन्य तरीकों से मुद्रा को प्रभावित करनेवाले प्रकरणों की जांच करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हों. तीसरा खंड भारत सरकार की खाद्य नीति और योजना के लिए विभिन्न राज्यों की खाद्य स्थिति की सूचनाएं एकत्र करके सरकार को देता रहता है. इसके अलावा अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं गैर कानूनी आवागमन पर नजर रख कर राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए सूचित करता है.

विधि प्रभाग भारत सरकार के विधि मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करता है. ब्यूरो द्वारा की जानेवाली जांच को कानूनी रूप से ठोस बनाने के लिए यह प्रभाग जांच अधिकारियों को आवश्यक सलाह देता है. किसी भी प्रकरण की जांच करने से पूर्व 'विधि अधिकारी' उसके सभी कानूनी पहलुओं का विश्लेषण कर, अपराध के तथ्यों के संग्रह संबंधी निर्देश देते हैं.

नीति प्रभाग सी. बी. आई. को प्रभावित करनेवाली सामान्य नीतियों के निर्धारण और परिपालन का कार्य करता है. यह केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से विभागीय सतर्कता, भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान जैसी कार्रवाइयों में जुटा रहता है. इन अभियानों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेना होता है.

तकनीकी प्रभाग 'आर्थिक मशीनों' के कलपुर्जे कसता है—प्रभाग की जिम्मेदारी है, सरकारी विभागों और संस्थाओं के हिसाब-किताब के सूक्ष्म परीक्षण की. इस प्रभाग के अधिकारी आय कर, लोक निर्माण, रेलवे, डाक-तार विभागों से चुन कर रखे गये हैं. इनके अलावा विशेष योग्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट भी प्रभाग में नियुक्त हैं. हाल ही में इस प्रभाग के साथ एक इंजीनियरिंग अनुभाग और जोड़ा गया. निर्माण कार्यों में होनेवाली गड़बड़ी की जांच के लिए इसका गठन हुआ है.

अपराध अभिलेख प्रभाग कुख्यात अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों एवं खतरनाक अपराधों की विस्तृत जानकारी रखता है. इसके लिए राज्य पुलिस इसे सहयोग देती है. यह काम सह[...]
आधुनिक मशीनों और तकनीकों [...]
'व्यापक तालिका' तैयार की जाती [...]
नोट और सिक्कों के निर्माण और प्र[...]
के लिए इस प्रभाग की भूमिका महत्व[...]
नकली मुद्रा सारे आर्थिक ढांचे को [...]
इस दृष्टि से प्रभाग द्वारा नोट और [...]
जानकारी एकत्र करने का काम लि[...]

किसी भी अपराध का मूल का[...]
पूरक होता है. कई अपराधी कभी [...]
हो कर पुलिस की नाक में दम कर[...]
आई. का **सांख्यिकी प्रभाग** पुलिस[...]
इस प्रभाग में अपराध और अपरा[...]
आंकड़े और ब्यौरे उपलब्ध हैं. इनके[...]
से अव्यवस्थित रूप में प्राप्त ब्यौरों [...]
क्रमबद्ध कर लेता है. साथ ही इन्हीं [...]
साहित्य के प्रकाशन और वितरण, [...]
चोरी, गैरकानूनी रूप से हथिया[...]
का निर्माण जैसे प्रकरणों संबंधी [...]
दिन में प्रकाशित करता रहता है. [...]
हत्याओं और आत्महत्या के मामलों [...]
करके **शोध प्रभाग** तक पहुंचा दी जा[...]

सामाजिक सुरक्षा का दायित्व [...]
भारत की पुलिस सदैव कठिना[...]
अपराधियों द्वारा अपना काम अधि[...]
जाने लगा है. उनके पास सुदूर बड़े [...]
में बैठ कर माल खपाने के साधन[...]
का मुकाबला करने के लिए अब तक [...]
समस्याओं का अध्ययन कर उ[...]
करता था, लेकिन अब यह 'पुलि[...]
सुपुर्द कर दिया गया है.

भारत 'इंटरपोल' (इंटरनेशन[...]
आर्गेनाइजेशन) का सदस्य है, व[...]
राधों की रोकथाम मुश्किल हो जाये[...]
मुखिया या सोना ले जा कर कोई [...]
तो भारतीय पुलिस चुप कर नहीं [...]
कोई विदेशी अपराधी भारत में [...]
शरण ले ले, तो इतने बड़े देश में [...]
है ! इंटरपोल का सदस्य होने के[...]
धियों की खोजने और दंडित [...]
संबंधित सभी देशों में सूचनाओं का [...]
इसी आदान-प्रदान के अंतर्गत [...]
मामलों में भारत ने विदेशी पुलि[...]
जब कि विदेशों से १४० प्रकरण [...]
लिए प्राप्त हुए. इस तरह नियमित[...]
का लेने-देन चलता है. सी. बी. आ[...]
पर यह राज्यों की पुलिस अपरा[...]
देता है, ताकि अपराधी को ढूंढने में [...]

सी. बी. आई. का **प्रशासन** प्र[...]
करण, भर्ती, प्रशिक्षण और सुधा[...]
करता है. सी. बी. आई. के पास [...]
अधिकारी, वैज्ञानिक और विशे[...]

आलोक मेहता : युवा पत्रकार. शैक्षणिक काल से ही पत्रकारिता और सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी अभिरुचि. इंदौर के दैनिक 'नई दुनिया' के संपादकीय विभाग में रह कर पत्रकारिता का अनुभव पाया. अब दिल्ली में 'हिंदुस्तान समाचार' के संवाददाता. इसके अलावा प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में प्रदेशों की राजनीति और विवादास्पद विषयों पर स्वतंत्र लेखन.

[illegible] का चयन राज्यों की पुलिस में भी किया जाता है. इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभाग के प्रतिनियुक्त श्रेष्ठ विशेषज्ञों को सी. बी. आई. में नियुक्त कर दिया जाता है. यह एक दुखद और हास्यास्पद सत्य है कि अपराधों की रोकथाम के लिए कुल-मिलाकर प्रशासन अपने 'योग्य' विशेषज्ञों और कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं देता. अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उन्हें रहने के लिए न मकान मिलते हैं, न ही अन्य सुविधाएं. फिर इस सेवा में रह कर उन्हें [illegible] करने का मौका भी नहीं मिलता.

महत्वपूर्ण अपराधों की खोजबीन का दायित्व उन पर है, लेकिन साधन और प्रशिक्षण सुविधाएं नाममात्र की. दुनिया के अन्य किसी भी देश के अन्वेषण ब्यूरो के मुकाबले सी. बी. आई. के पास साधन नहीं के बराबर हैं. यहां तक कि सी. बी. आई. के अधिकारियों द्वारा [illegible] लाने के लिए उपयोग में लायी जानेवाली अनेक 'जीप-कारें' जर्जर और पुरानी हैं, जबकि आधुनिक [illegible] तस्कर शानदार तथा नयी कारों में चलते हैं.

सी. बी. आई. की ओर से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए समय-समय पर जनता से सहयोग की अपेक्षा की जाती है. हाल ही में एक फिल्म भी बनायी गयी है. सी. बी. आई. के कार्यकरण पर शोर है बहुत, लेकिन इसके प्रशासन में हिंदी का उपयोग केवल सरकारी [illegible] है. एक उच्च हिंदी अधिकारी के नेतृत्व में हिंदी [illegible] कार्य करता है. लेकिन जनता से सहयोग के लिए प्रकाशित-प्रसारित होनेवाली अधिकांश सामग्री अंग्रेजी में होती है. यह मान कर कि शायद अंग्रेजी [illegible] 'भ्रष्ट अधिकारी' ऐसे परिपत्रों से भयभीत हो जायें 'पूरी ईमानदार' [illegible].

[illegible] यह अवश्य उल्लेखनीय है कि हिंदी में प्राप्त [illegible] पत्रों के उत्तर हिंदी में दे दिये जाते हैं. हिंदी [illegible] बढ़ाने के संबंध में सरकारी भाषा विभाग [illegible] की त्रैमासिक बैठक भी होती है. फिर भी [illegible] का रास्ता सी. बी. आई. से पड़ता है, उसका [illegible] है कि हिंदी में पत्र देने पर वह कई दिनों तक 'लाल फीते' में बंधा हुआ इस मेज से उस मेज तक घूमता है.

अपराध की जांच : सजा कब ?

सी. बी. आई. की प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत एक निदेशक सर्वोच्च अधिकारी है. इनके साथ तीन संयुक्त निदेशक हैं. इनके अलावा करीब दो सौ अधिकारी हैं. सी. बी. आई. के लिए स्वीकृत ३८३ निरीक्षकों के स्वीकृत पदों में ६४ अभी तक रिक्त हैं. निरीक्षकों और कर्मचारियों की कमी के कारण १९७३ में ३६ जटिल मामलों की जांच-पड़ताल में दो वर्ष से भी अधिक समय लगा. कहा जाता है कि राज्यों की पुलिस में से योग्य व्यक्ति नहीं मिलने के कारण ये पद खाली हैं. ये 'योग्य' लोग कहां से आ जायेंगे? संभवतः प्रशासन भी नहीं जानता.

इसे भारत की दोषपूर्ण व्यवस्था कहा जाये या [illegible], कि सी. बी. आई. चाहे बड़े-बड़े धावे मारे, रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़े, हत्यारों पर से पर्दे उठाये, लेकिन वह अपराधियों को दंडित तो कर नहीं सकती! परिणामस्वरूप वर्षों तक मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े रहते हैं और अपराधी मजे में. इस बात का प्रमाण है—वर्ष १९७३ के अंत तक १,३७४ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित रहना. इनमें से कुछ प्रकरण तो १९६२ से लटके हुए हैं. बीस मामले दस वर्षों से लंबित हैं और इस दौरान अभियोजन के कई गवाह मर चुके हैं, तो कई के नये पते न मिलने से प्रकरण उतने गंभीर नहीं रहे, जितने कि तूफानी जांच के दौरान थे.

एक मजेदार तथ्य है सी. बी. आई. की १९७३ की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकारा जाना कि न्यायालय में विशेषतः उन प्रकरणों में देरी होती है, जिनमें साधन संपन्न और धनी अभियुक्त अंतर्ग्रस्त होते हैं. मतलब यह कि भ्रष्टाचार या अन्य गैरकानूनी तरीकों से पैसा बनाइए, मजा कीजिए और शायद आपको सजा अगले जन्म में मिले.

इसीलिए कई लोग सी. बी. आई. से इसलिए नाराज हैं कि वे अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने में सहयोग तो देते हैं, लेकिन अपराधी दंडित नहीं होता. यहां तक कि दंडित नहीं होने पर अपराधी शिकायतकर्ता को जरूर 'दंड' दे जाता है.

बचना है मुश्किल इन नजरों से

चोर, डाकू हो या नकली मुस्कान के साथ दोस्ती का हाथ, सी. बी. आई. को चकमा दे कर अपराधी बच नहीं सकता. सी. बी. आई. के अधिकारियों की मानवीय आंखों पर अपराधी धूल झोंक सकता है, लेकिन इस संगठन की वैज्ञानिक नजरें अपराध के बिलकुल गहरे कोने तक पहुंच ही जाती हैं. संख्या और साधनों की कमी होने पर सी. बी. आई. के अधिकारी चाहे किसी जटिल प्रकरण की खोज में अधिक समय न लगा पायें, किंतु अपराधी द्वारा छोड़े गये छोटे-से-छोटे चिह्न सी. बी. आई. की वैज्ञानिक नजरों द्वारा साफ कर के अपराधी का सही रूप सामने ला देती हैं. ये नजरें हैं—फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आधुनिक उपकरणों से सज्जित इस लेबोरेटरी के न होने से सी. बी. आई. या भारत के अन्य पुलिस संगठन अपराधियों द्वारा छोड़े गये निशानों की पुष्टि के लिए भटकते थे. अधिक महत्वपूर्ण प्रकरण होने पर विदेशों की प्रयोगशालाओं में भेज कर इन चिह्नों से निकलनेवाले निष्कर्ष का पता लगाया जाता था. इस तरह जांच-पड़ताल में देरी होने से अपराधी तक पहुंचने में और अधिक कठिनाई आती. देर से ही, किंतु सरकार ने यह आवश्यक समझा कि देश की राजधानी दिल्ली में ही केंद्रीय फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना कर दी जाये. करीब तीन वर्ष से लेबोरेटरी ने कार्य प्रारंभ किया है और अपराधियों तक पहुंचने एवं न्यायालय में प्रकरण सिद्ध करने में सी. बी. आई. को महत्वपूर्ण सहयोग दिया.

केंद्रीय फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जैविकी, रसायन, भौतिकी, अन्य विज्ञान और दस्तावेज संबंधी जांच विभाग हैं. इसमें है—एक फोटोग्राफी प्रभाग [...] जिसमें वैज्ञानिक जानकारी. भौतिकी प्रभाग में पेंट, धातुओं आदि के विश्लेषण करनेवाला 'स्पेक[...]' है, जिसकी सहायता से बड़े पैमाने पर होनेवाली [...] की चोरी को पकड़ा गया.

इसी तरह जैविकी विभाग में हत्या के [...] की जांच हेतु खून, दांत, बाल जैसे छोटे-से-छोटे [...] की बारीकियां उभार ली जाती हैं. बलात्कार [...] में मृत्यु, आत्महत्या या हत्या में जहर अथवा [...] दवाइयों के उपयोग को स्पष्ट करनेवाले उपकरण इस विभाग में उपलब्ध हैं.

रसायन विभाग में अफीम, धतूरा, [...] नमक, दवाइयां, अल्कोहल, शीशे के चूर्ण [...] परीक्षण की व्यवस्था है.

लेबोरेटरी में अंगुलियों के निशान, नकली [...] धर, गोला-बारूद इत्यादि के परीक्षण का भी [...] है. कौन-सी गोली किस बंदूक से चली, इसकी [...] लेबोरेटरी में संभव है.

लेबोरेटरी के विभिन्न विभागों में योग्यता [...] विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता कार्यरत हैं. [...] रेटरी में उपलब्ध उपकरणों से वे अपराध की [...] तक पहुंचा देते हैं, फिर भी इस तथ्य से इंकार नहीं [...] जा सकता कि अपराधों की संख्या में दिन-दिन [...] वृद्धि को देखते हुए ये साधन कम पड़ते जा रहे हैं.

दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों में भी [...] छोटी लेबोरेटरियां हैं, लेकिन वे भी समस्याओं से [...] हुई हैं. इसका प्रमाण मिला हाल ही में हुए फा[...] साइंस लेबोरेटरी के निदेशकों के सम्मेलन में. यहां [...] विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत का [...] नहीं. अन्य वैज्ञानिकों की तरह प्रशासकीय तंत्र से [...] वाली परेशानी कोई राज्य पुलिस के मातहत, [...] केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, सुरक्षा मंत्रालय की [...] रेटरी में कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों की जिम्मे[...] केवल शोध, प्रयोग और परीक्षण करना. जब कि [...] सिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को अपने [...] की पुष्टि करना भी आवश्यक. अधिक जिम्मेदारी [...] उपकरणों की कमी, प्रयोगशालाओं में सुधार [...] केंद्र सरकार को भेजे जानेवाले पत्रों के उत्तर नहीं.

इस सबके बावजूद गृह राज्यमंत्री का [...] भाषण-"अपराधों को रोकने के लिए फारेंसिक [...] लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण भूमिका [...] करनी होगी. यह उनके सामने ही नहीं, संपूर्ण समाज [...] राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती है." (२० अप्रैल, १९[...]

एक निदेशक ने अपने पास बैठे हुए साथी से [...] 'मुकाबला करिए चुनौती का. जरूरी सामान [...] मूल कर्मचारियों के बस पर." एक निदेशक ने खुद [...] आरोप लगाया— पत्रों के जवाब आते नहीं. राज्य [...] पुलिस से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता.

दूसरे निदेशक ने बताया—न्यायालय में भी [...] लेबोरेटरी की पुष्टि को प्रमाणित नहीं माना [...] तमिलनाडु में हाल ही में न्यायालय ने एक प्रकरण [...] सुनवाई के दौरान निर्णय दिया कि राज्य पुलिस के [...] कार्यरत लेबोरेटरी की रिपोर्ट निष्पक्ष कैसे हो [...] है! पुलिस का पक्ष मजबूत करने के लिए प्रमाणों को [...] का प्रयास किया गया है. इस तरह एक नया वैज्ञानिक [...] उत्पन्न हो गया है, उपाय खोजा जाना चाहिए.

अभी तक तो फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी के [...] प्रमाण और निष्कर्ष को न्यायालय में माना जाता [...], किंतु यदि तमिलनाडु की तरह ही अन्य न्यायालय भी ऐसे प्रश्न उठाने लगे, तो सी. बी. आई. अपने [...] की पुष्टि कैसे करवाएगी?

लेबोरेटरी की वैधानिक मान्यता के लिए सर[...] संभवतः आवश्यक कार्रवाई करेगी. सरकार लेबोरेटरी के महत्व को समझने लगी है. इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत लेबोरेटरी को वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए करीब [...] करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी. प्रगति के संके[...] अच्छे हैं, परिणाम भविष्य ही बताएगा. ■

दस्तावेजों में धोखाधड़ी: बायीं ओर— सामान्य प्रकाश में एक दस्तावेज और दायीं ओर— मिटायी गयी पंक्तियां अल्ट्रा वायलेट प्रकाश में स्पष्ट नजर आ रही हैं.

भ्रष्टाचार

मिलिए, सी. बी. आई. के निदेशक देवेंद्र सेन से

ज़रा अंदाज लगाइए, कैसा व्यक्तित्व होगा सी. बी. आई. [illegible] का? भयंकर, रोबवाला, विशालकाय [illegible] कड़ी आवाज! बड़ी मूंछें और सामने [illegible] डर लगा! जी नहीं, इस तरह के फिल्मी [illegible] नयी दिल्ली के नार्थ ब्लाक में सी. बी. आई. के निदेशक के कमरे में पहुंचने पर आप चौंक [illegible] सहसा विश्वास नहीं होता कि हम सही व्यक्ति [illegible] पास पहुंचे हैं. चेहरे पर मीठी-सी मुस्कराहट, तपस्वी-सी सौम्यता और बातचीत में अपनापन.

[illegible] और गहराई में जाएं, तो पता चलेगा कि सी. बी. आई. के निदेशक श्री देवेंद्र सेन, केवल इस [illegible] के वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं, संस्थापकों में से एक हैं. वे इस संगठन में इतने रम गये हैं, जैसे यही उनका घर-[illegible]-जीवन और आदर्श है. जानते हैं, इन प्रेरणा [illegible] स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री को है. गृह-मंत्री के रूप में शास्त्री जी काफी परेशान रहते थे, भ्रष्टाचार की शिकायतों से. अंतर्राज्यीय अपराधों की [illegible] के लिए, इच्छा थी कि कोई निर्विवाद संगठन [illegible] जिस पर सरकार के अलावा जनता और न्यायालय [illegible] पूरा विश्वास हो सके. उनकी चिंता ऐसे अधि-[illegible] सामने भी आयी, जो शास्त्री जी को बहुत [illegible] करते थे. ऐसे ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री देवेंद्र सेन ने अमरीका के 'फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टी-गेशन' (एफ. बी. आई.) को आधार बना कर आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) की स्थापना की सलाह शास्त्री जी को दी. विचार मान गया और १९६३ में वैधानिक रूप से सी. बी. आई. का गठन भी हुआ. हां, [illegible] का काम पूरा होने पर देवेंद्र सेन को निदेशक [illegible] मिला १९७१ में. फिर भी अन्य सहायक पदों पर रहते हुए श्री सेन ने शास्त्री जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए सी. बी. आई. को सौंपे गये कई जटिल प्रकरणों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब श्रीमती इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में वे सी. बी. आई. को जनता में अधिकाधिक विश्वसनीय बना पाने में सफलता पा रहे हैं.

और, यह तो हुई व्यक्तिगत बात. धर्मयुग के पाठकों तक सी. बी. आई. की कार्यप्रणाली पर बातचीत के लिए मैं जब श्री सेन के पास पहुंचा, तो शुरुआत शंकाओं से हुई.

"बड़ा भ्रम है, सी. बी. आई. के संबंध में. आखिर कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच से सी. बी. आई. इंकार क्यों कर देता है?"

"यह ठीक है कि कई प्रकरण वापस कर दिये जाते हैं, क्योंकि एफ. बी. आई. की तरह सी. बी. आई. का दायित्व सभी तरह के राष्ट्रीय अपराधों की जांच करना नहीं है," श्री सेन ने बताया, "वास्तव में सी. बी. आई. की प्रमुख जिम्मेदारी आर्थिक और अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच करना है. फिर भी राज्य पुलिस के सीमित साधनों और राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न होने पर हत्या, डकैती और बड़ी चोरी के प्रकरण भी सी. बी. आई. संभालता है. वरना, राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन, अधिकारी हो या नेता, अधिकांश मामलों में सी. बी. आई. की जांच का आग्रह किया जाता है. सरकार भी कई प्रकरण हमारे पास भेज देती है, लेकिन यह अंतिम निर्णय तो हम ही करते हैं कि संबंधित प्रकरण सी. बी. आई. के दायरे में आता है या नहीं."

"सेन साहब, यह तो इस बात का प्रतीक है कि शास्त्री जी के सपने के अनुसार सी. बी. आई. पर जनता का बहुत विश्वास है?"

"जी हां, आप ऐसा कह सकते हैं. वैसे यह अनुभव हुआ है कि पहले तो कोई गंभीर मामला सी. बी. आई. को सौंपने की मांग की जाती है, लेकिन मांग करनेवालों के अपने अनुमान के अनुसार जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आने पर वे इस पर अविश्वास करने लगते हैं. जैसा जनसंघ अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच के बाद हुआ. हत्या के इस प्रकरण की काफी बारीकी से जांच करने के बाद सी. बी. आई. का निष्कर्ष यह था कि हत्या सामान्य चोरी करनेवाले अपराधियों ने की. अपराधी सामान ले कर ट्रेन के उस डिब्बे के दर-वाजे पर खड़े हुए थे और श्री उपाध्याय के अचानक बाथरूम से निकलने पर अपराधी घबरा गये. श्री उपाध्याय ने उन्हें अगले स्टेशन पर पुलिस के सु[illegible] करने की चेतावनी दी. इस पर अपराधियों ने श्री उ[illegible] ध्याय की हत्या कर दी और अगले स्टेशन पर चुप[illegible] उतर गये. कई लोगों ने इस जांच का विश्वास नहीं कि[illegible]

"अब आप ही बताइए कि हम मांगकर्ताओं [illegible] इच्छानुसार अपनी रिपोर्ट दें, तो सी. बी. आई. [illegible] कौन विश्वास करेगा? अतः हम चाहते नहीं हैं [illegible] किसी भी दबाव से अनावश्यक जांच नहीं कर[illegible] जानी चाहिए.

"एक अनावश्यक जांच का मजेदार उदाहरण [illegible] एक बार एक ऐसा प्रकरण हमारे पास भेजा गया, जि[illegible] यह जांच करने का आग्रह था कि एक स्थान पर [illegible] वर्ष पूर्व पेड़ लगाये जाने का हिसाब दर्शाया गया [illegible] वास्तव में वे पेड़ नहीं लगाये गये थे. अब यह पता [illegible] एए कि वे पेड़ लगे या नहीं? जरा सोचिए, [illegible] पूर्व पेड़ लगाने की सत्यता या असत्यता को हम [illegible] सिद्ध करते? अतः हमने इसकी जांच से इंकार [illegible] दिया."

"सेन साहब, सी. बी. आई. का गठन एफ. बी. [illegible] के आधार पर हुआ, लेकिन यह सभी केंद्रीय मह[illegible] मामलों की जांच क्यों नहीं करता?"

"आधार का मतलब नकल नहीं होता. हमने सी. [illegible] आई. का कार्यक्षेत्र अपने देश की परिस्थितियों के [illegible] बना रखा है. संविधान के अनुसार अपराधों की [illegible] थाम और कानून-व्यवस्था का कार्य राज्यों के अ[illegible] क्षेत्र में है. अमरीका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्[illegible] गेशन का अधिकार क्षेत्र बहुत विशाल है. १९[illegible] स्थापित एफ. बी. आई. को १८५ तरह के उन अ[illegible] की जांच का अधिकार मिला, जो संघीय [illegible] का उल्लंघन करने के अंतर्गत आते हैं. इसके [illegible] अमरीका के प्रत्येक क्षेत्र में एफ. बी. आई. [illegible] और कर्मचारी अलग से कार्यरत हैं. साथ ही ५[illegible] डिवीजन कार्यालय भी बनाये गये हैं. जबकि [illegible] यहां कुछ निश्चित और विशेष अपराधों की [illegible]

सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों पर सी. बी. आई. द्वारा चलाये गये भ्रष्टाचार व अनियमितता के प्रकरण

विभाग और पद	प्रकरणों की संख्या वर्ष १९७२	१९७३
(१) सुरक्षा सेवाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारी	२१	४३
(२) विभिन्न विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के इंजीनियर	१२२	८३
(३) रेलवे अधिकारी	४४	३९
(४) सचिवालय अधिकारी	१५	४
(५) एक मंत्रालय के सहायक निदेशक	२	२
(६) आयात-निर्यात नियंत्रक	६	११
(७) आय कर विभागों के अधिकारी	२२	२८
(८) एक्साइज और कस्टम अधिकारी	१२	४०
(९) सार्वजनिक संस्थानों और स्वायत्त निगमों के वरिष्ठ अधिकारी	५	१२
(१०) विभिन्न विभागों के प्रथम श्रेणी के अधिकारी	१५१	१३०
(११) विभिन्न विभागों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	१३९	२०५
(१२) राज्य सरकारों के अधिकारी	३०	४६
	५८९	६४९

सी. बी. आई. से राजकोष को हुई आय

माध्यम	१९७२	१९७३
(१) सी. बी. आई. के विशेष पुलिस संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से हुए जुर्माने	३१,९७,७३१	१५,७२,३१९
(२) विशेष पुलिस की रिपोर्ट पर सार्वजनिक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से वसूली	१,२७,७३५	६५,७३४
(३) अधिक अदायगी की वसूली	२७,५९१	००,००,०००
(४) चोरी किये गये आय कर या बिक्री कर की वसूली	४,६७,६२३	१,२८,५५,२०३
(५) सी. बी. आई. के प्रयासों से हुई बचत	७०,७२,८१०	५०,२४०
कुल	१,०८,९३४९३	१,४५,४२४९८

सी. बी. आई. द्वारा दो वर्षों (१[illegible] एवं १९७३) के दौरान न्यायाल[illegible] सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध [illegible] किये गये प्रकरण

मंत्रालय के नाम	सरकारी कर्मचारी राजपत्रित	अराजपत्रित	सार्वजनिक [illegible] के [illegible] राजपत्रित
(१) संचार	१	१११	००
(२) सुरक्षा	१४	९	००
(३) वित्त	१६	३१	१७
(४) रेलवे	४	१७४	१
(५) वाणिज्य	२	११	१
(६) औद्योगिक विकास	००	२	७
(७) इस्पात और खान	१	१	६
(८) पेट्रोलियम और रसायन	४	१	७
(९) संघीय क्षेत्रों के कर्मचारी	३	८	००
(१०) राज्य सरकारों के कर्मचारी	२२	२९	१
कुल	६७	३७७	४१

गृह राज्यमंत्री रामनिवास मिर्धा :
सी. बी. आई. के नीति निर्धारक

स्व. लालबहादुर शास्त्री की प्रेरणा :
सी. बी. आई. की स्थापना

देवेंद्र सेन : निदेशक सी. बी. आ

जिम्मेदारी सी. बी. आई. को १९६३ में ही मिली. भारत में सामान्य अपराधों की जांच राज्य पुलिस का पुलिस विभाग तथा राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच 'इंटेलीजेंस ब्यूरो' करता है."

"पिछले चार-पांच वर्षों में देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में हुए अनेक परिवर्तनों के दौरान सी. बी. आई. के कार्यकरण में भी प्रगति हुई या नहीं?"

"बहुत अधिक!" श्री सेन ने तपाक से जवाब दिया. "देश के सर्वोच्च नेताओं ने पिछले वर्षों में सी. बी. आई. की कार्यकुशलता में वृद्धि और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए गहरी रुचि दिखायी है. विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सी. बी. आई. में रुचि लेना इस संगठन के वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है. श्रीमती गांधी की रुचि का ही यह परिणाम है कि सी. बी. आई. के कार्य में तत्परता लाने और राज्यों से बेहतर तालमेल रखने के लिए सी. बी. आई. का प्रशासनिक कार्य १९७१ में गृह राज्यमंत्री श्री रामनिवास मिर्धा के सुपुर्द कर दिया गया. यह दायित्व संभालने के बाद श्री मिर्धा ने सी. बी. आई. की कठिनाइयों का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है."

"श्रीमती गांधी ने प्रशासनिक सुधार के अलावा कोई रचनात्मक सुझाव भी सी. बी. आई. के लिए दिया?"

"जी हां, समय-समय पर सी. बी. आई. के कार्यों में सुधार के लिए श्रीमती गांधी ने हमारा मार्गदर्शन किया. जैसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए श्रीमती गांधी ने सी. बी. आई. को एक विशेष यूनिट गठित करने की सलाह दी. इसी तरह राज्यों द्वारा भेजे जानेवाले प्रकरणों को निपटाने के लिए भी दो विशेष यूनिटों की स्थापना उन्हीं की सलाह का परिणाम है. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है—भारतीय पुरातत्व की दुर्लभ वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए श्रीमती गांधी द्वारा एक यूनिट अलग से गठित करने का निर्देश देना. इस यूनिट की सक्रियता के परिणामस्वरूप ही चंबा से चोरी गयी बहुमूल्य मूर्ति की पुष्टि बंबई में खोज ली गयी. खजुराहो से चुरायी गयी मूर्तियां ढूंढ़ी जा सकीं. बिहार के एक संग्रहालय से चुरायी गयी मुगलकालीन पांडुलिपि एवं दुर्लभ चित्र खोजे जा सके. ऐसी कितनी ही उपलब्धियां गिनायी जा सकती हैं."

"आपके कार्यकाल में सर्वाधिक बड़ा एवं रोचक कौन-सा प्रकरण सी. बी. आई. के सामने आया?"

"हमारे लिए तो हर मामला ही महत्वपूर्ण और रोचक होता है. वैसे राष्ट्रीय संग्रहालय में हुई चोरी का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर की गयी जांच और हाल में ही एक उद्योग द्वारा करोड़ों की गड़बड़ी करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गयी खोजबीन काफी रोचक हैं, जो उल्लेखनीय कही जा सकती हैं."

"आप प्रत्येक मामले को महत्व देते हैं, लेकिन सी. बी. आई. के १९७३ के प्रतिवेदन में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि काफी बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के स्थान रिक्त हैं. इसके प्रमुख कारण और हल क्या हैं? क्या कर्मचारियों की कमी से सभी प्रकरणों की जांच उचित समय पर पूरी होने में रुकावट नहीं आती?"

"जी हां, यह सच है कि इंस्पेक्टर के ६४ पद रिक्त हैं, क्योंकि इसके योग्य व्यक्ति मिले नहीं. आप शायद पुनः शंका करेंगे कि इतने बड़े देश में सी. बी. आई. के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलना कैसे असंभव है? इसलिए मैं आपको बता दूं कि सी. बी. आई. पचास प्रतिशत नियुक्ति सीधी भर्ती और पचास प्रतिशत राज्यों से 'डेपुटेशन' पर करती है. यह तो आप मानेंगे कि सी. बी. आई. की जांच का कार्य अत्यंत कठिन, बारीक और महत्वपूर्ण होता है. इस कारण विज्ञापित करने पर भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलते. इसी तरह राज्यों से भी श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनना कठिन होता है. फिर योग्य व्यक्ति मिलने पर यहां आने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे आवास एवं अन्य सुविधाएं यहां नहीं मिलतीं. इसी दृष्टि से हाल ही में हमने सरकार को इन कर्मचारियों की आवास-व्यवस्था करने के लिए लिखा और इस दिशा में कुछ शुरुआत भी हो गयी है. इसके अलावा श्रेष्ठ कर्तव्यपरायणता के लिए सी. बी. आई. के कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिये जाने लगे हैं. सी. बी. आई. के १,१५५ कर्मचारियों को पिछले वर्ष के दौरान श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत करने हेतु ५६,३१२ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी. वर्ष १९७२ में सी. बी. आई. के उप पुलिस अधीक्षक श्री के. ए. राजगोपालन को सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारी के रूप में मुहम्मदी का स्वर्ण पदक और एक हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया. १९७३ के गणतंत्र दिवस पर श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सी. बी. आई. के २५ से अधिक कर्मचारियों को राष्ट्रपति द्वारा सेवा पदक दिये गये. इससे सब कर्मचारी प्रोत्साहित होते हैं. अतः यह कहना भी गलत होगा कि कर्मचारियों की कमी के कारण सी. बी. आई. के पास प्रकरण अधिक समय तक अटके रहते हैं."

"चलिए, हम यह मान भी लें कि सी. बी. आई. के दक्ष कर्मचारी फुर्ती से अपनी जांच पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि जांच पूरी होने के बावजूद अपराधी को समय पर दंडित करने का लक्ष्य पूरा नहीं होता? आपकी ही रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां तक कि कई प्रकरण दस वर्ष से भी अधिक समय से अटके हुए हैं?"

"आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया है. इसके अनेक पहलू हैं और जिम्मेदारी कम-से-कम हमारी है भी नहीं. जांच पूरी कर लेने के बाद हम उसे न्यायालय में दाखिल कर देते हैं. इसके बाद संबंधित व्यक्ति या संस्थान विभिन्न कानूनी दांव-पेंच लगा कर इसकी सुनवाई टालता रहे, तो इसमें हमारा दोष क्या हो सकता

"फिर भी इतने वर्षों में आपने सरकार के ऐसी कोई योजना नहीं रखी, जिससे सी. बी. प्रकरण जल्दी निपटाने आदि का प्रावधान जा सके?"

"एक नहीं, अनेक. आज नहीं, कई वर्षों तो १९६४ में ही 'सी. बी. आई. अधिनियम' करके इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की योजना को भेजी थी. इसके बाद भी समय-समय पर आई. के कार्यकरण में सुधार के प्रस्ताव भेजे कुछ स्वीकारे गये, कुछ विचाराधीन हैं. हां, के अनुसार कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होने के कारण सी. बी. आई. अधिनियम में के लिए संविधान में भी संशोधन करना आव अतः सरकारी एवं अन्यान्य कारणों से यह क्रियान्वित नहीं हो पाया है. फिर भी हाल ही मात्र संशोधन द्वारा न्यायालय में विचाराधीन को अपील करने पर थोड़ा अंकुश लगाने की कानूनी रूप से हो चुकी है. इसके अलावा सी. बी की जांच के आधार पर दायर किये गये प्रकरण टाने के लिए दिल्ली में एक विशेष जज और एक रिक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त होने के परिणामस्वरूप पीस ३५० में से १८० प्रकरणों पर निर्णय हम अब सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं कि आई. से संबंधित सभी प्रकरणों को निपटाने के अलग से न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाये."

"किसी भी अपराध की शिकायत, जांच और लक्ष्य की सफलता के दौर से गुजरने की प्रक्रिया नागरिकों का सहयोग कैसे लेते हैं?"

"क्यों, जनता से हमारा संपर्क बना रहता संपर्क के विभिन्न माध्यमों—रेडियो, टेलिविजन, समाचारपत्र इत्यादि की सहायता से हम जनता विश्वास दिलाते हैं कि यह उनका अपना संगठन है. सूचना देने या सहयोग करने पर उन्हें कोई खतरा

"अंतिम सवाल है, आर्थिक अपराध अर्थात भ्रष्टाचार की जांच के लिए क्या एक सामान्य नागरिक की शिकायत पर भी आप ध्यान देते हैं? यदि हां, तो आप नागरिकों से और क्या अपेक्षा करते हैं?"

"यह एक भ्रांति है कि हम केवल सरकार द्वारा भेजे गये प्रकरण की ही जांच करते हैं. हमारे एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा स्वयं मेरे पास औसतन १५–२० पत्र शिकायतों के आते हैं. संभव है कि इनमें से हमारे कार्य क्षेत्र में आनेवाले महत्वपूर्ण प्रकरणों की जांच की जाती है. नागरिक हम यही चाहते हैं कि वे केंद्रीय सरकार से संबंधित मामले हमारे पास भेजें और जांच में सहयोग देने में हिचकिचायें नहीं. अब तो सी. बी. आई. की ओर से विशेष रूप से सहयोग देनेवालों को भी पुरस्कृत किया जाता है."

◻ आ